



E-ISSN: 2664-603X
 P-ISSN: 2664-6021
 IJPSG 2022; 4(1): 149-151
www.journalofpoliticalscience.com
 Received: 09-01-2022
 Accepted: 12-02-2022

विशाखा सिंह नेहा
 JRF, Political Science,
 University of Rajasthan,
 Jaipur, Rajasthan, India

नक्सलवाद : देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौति

विशाखा सिंह नेहा

सारांश

1967 में पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलबाडी में जमींदारों के खिलाफ अधियारबन्द आन्दोलन चलाया गया था। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी से अलग हुये एक धड़े ने नक्सल मूवमेंट के जनक माने जाने वाले चोरु मजूमदार के नेतृत्व में यह संघर्ष चलाया था। 1970 के दशक में किसानों की दशा कमजोर, दयनीय, बाल मजदूरी की अधिकता, बेरोजगारी में वृद्धि सामन्ती के अत्याचार की बढ़ती प्रवृत्ति भ्रष्टाचार एवं असमानता के खिलाफ इस आन्दोलन में लोग एकजुट हुये जो वर्तमान में साम्यवादी सरकारी की स्थापना तथा असमानता के खिलाफ संघर्ष के लये प्रयासरत है।

सर्वे के अनुसार भारत के 1 प्रतिशत लोगों के पास 73 प्रतिशत पैसा है जो की आय का अत्यधिक असमानता को प्रदर्शित करता है। सरकार के अनुसार अब नक्सलवाद देश के 11 राज्यों एवं 90 जिलों में फैला हुआ है। जो केवल 30 जिलों में अतिप्रभावी है। देश के जिन राज्यों में नक्सली हिंसा तीव्र उभार पर है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश और उड़ीसा। आम धारणा यही है कि इन राज्यों में नक्सलवाद उभार की वजह इनका अविकसित होना है। वर्तमान समय में सिर्फ गरीबी व पिछड़ेपन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है यह एक विचाराधारा है जिसे बाह्य समर्थन भी प्राप्त है। नक्सली आन्दोलन को राष्ट्र के लिये कभी भी चुनौती नहीं माना गया जबकि सर्वे के मुताबिक 2009 से 2021 तक नक्सली हमलों की संख्या तथा उनमें मारे गये नागरिकों व सैनिकों की संख्या जम्मू कश्मीर में हुये आतंकी हमलों की संख्या से अधिक है।

वर्ष 2012 में डॉ० मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद की देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ा खतरा बताया तथा नक्सलवाद के खिलाफ 'जीरो टोलरेंस' की नीति अपनाने पर बल दिया। ऐसे में नक्सली आन्दोलन के खिलाफ लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ अभियान से कहीं अधिक मुश्किल, दुरुह व चुनौतिपूर्ण है।

मूल शब्द: नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा, अधियारबन्द आन्दोलन

प्रस्तावना

नक्सलवाद क्या है।

चीन के साम्यवादी दल की विचाराधारा से प्रभावित भारत के साम्यवादी विचाराधारा पर अमल करने वाले लोगों ने पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाडी, हमारबाडी, तुमारबाडी आदि छोटे ग्रामीण स्थानों से नक्सलवाद की शुरुआत मानी जाती है।

1970 के दशक में अपनी जमीन पर नाजायज तरीके से आधिपत्य के कारण वहां के किसानों के भस्वामियों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत कर दी। इन किसानों को साम्यवादियों का प्रत्यक्ष समर्थन मिला। इस प्रकार की विचाराधारा से प्रभावित होकर एक हिंसक आन्दोलन का जन्म हुआ जिसे नक्सलवाद कहा जाता है।

नक्सलवादी विचाराधारा –

नक्सलवाद मार्क्सवादी और माओवादी विचाराधारा का पालन करता है, जो अपने अधिकारों की मांग को पूरी करवाने के लिये सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करते हैं। शुरुआती समय में नक्सलवाद एक तरह का भूस्वामियों में अत्याचार के विरुद्ध आदिवासी किसानों द्वारा आरम्भ किया गया एक किसान आन्दोलन था जो अब पूर्ण सिस्टम का विरोधी बनकर हर मुमकिन अवसर पर हिंसा पर उतारू है। गरीबी के खिलाफ होने वाली राज्य, वर्गों और जातियों की हिंसा तथा दमन, उत्पीडन से मुकाबला करने उसका सशस्त्र जवाब देने की इजाजत देती है। युवा नक्सलवादी आन्दोलन को सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी आन्दोलन के रूप में देखते हैं। नक्सलवाद के प्रति राज्य का रवैया मुख्य रूप से आग लगाने के कारणों को समाप्त करने के बजाय कहीं आग लग जाने पर उसे बुझाने के लिये दौड़ने का है। नक्सलवादी आज भी अपने अंतिम लक्ष्य क्रांति से हटे नहीं हैं लेकिन व्यवहार से उनकी मुख्य गतिविधियां अपने क्षेत्र की जनता के हितों के लिये लड़ना दूसरे गुटों को भी ऐसा करने में सक्षम बनाना और यह गारन्टी देना है कि हिंसात्मक स्थिति पैदा होने पर जब भी उनकी

Corresponding Author:
विशाखा सिंह नेहा
 JRF, Political Science,
 University of Rajasthan,
 Jaipur, Rajasthan, India

जरूरत पड़ेगी वे उपलब्ध होंगे । गरीब मेहनतकश जनता उन्हें अपना अंतिम व सबसे बड़ा रक्षक मानते हैं। नक्सवादी संसदीय रास्ते को गरीब जनता के लिये उपयोगी नहीं समझते

अर्बन नक्सलवाद –

शहर में रहने वाले तमाम किस्म के लोग जो मौजूदा सत्ता का विरोध कर रहे हैं । इसमें मार्क्सवादी, समाजवादी, उदारवादी, मानवाधिकारवादी, पत्रकार, लेखक, वकील शामिल हैं। यह माओवादियों की एक तरह की रणनीति होती है जिसमें शहरों में नेतृत्व तलाशने, भीड़ जुटाने, संगठन बनाने और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें तमाम चीजे, सामग्रीयों के साथ-साथ प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है । इस रणनीति के तहत शहरी क्षेत्रों में नेतृत्व तलाशने की कोशिश की जाती है। यह संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ इसे बड़ा बनाने पर भी बल देते हैं। सभी सेक्यूलर ताकतों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिन्दू कासीवादी ताकतों के खिलाफ खड़ा किया जाये ।

नक्सलवाद के कारण –

आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित लोगों का सरकार के प्रति असम्मानजनक दृष्टिकोण है सामाजिक बुराईया यथा गरीबी, कुपोषण बेरोजगारी अशिक्षा के कारण पिछले इलाकों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है वंचित वर्गों के लिये विशेष योजनाओं का अभाव यदि योजनाये है तो उनके समुचित क्रियान्वयन का अभाव होने के कारण असली हकदार लोगों तक इनका फायदा नहीं पहुंच पाया। नक्सलवाद की शुरुआत का मूल कारण स्थानीय जमींदारों के अत्याचार और भूमि अधिग्रहण के कारण उत्पन्न बेरोजगारी है। सरकार की रणनीतिक अस्पष्टता और नीतिगत विरोधाभास ने भी इसे बढ़ावा दिया है।

नक्सलियों की क्षमताएँ यथा उनकी रणनीतिक सफलताएँ तैयारी का दौर जिसमें वे अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं एवं समर्थकों की संख्या में वृद्धि करते हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा सर्वहारा गणतंत्र की स्थापना जिसमें स्वतंत्र सरकार व जन अदालत शामिल है जिनका संसाधनों पर नियंत्रण है एवं जनजातियों को प्रभावित करती है। नीजिकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण को बढ़ावा दिये जाने के फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गयी तथा विकास के नाम पर आदिवासियों एवं उनके संसाधनों का दोहन होने लगा । जिससे लाल गलियारा (नक्सल प्रभावित क्षेत्र) में वृद्धि हुई जो पशुपति से तिरुपति अर्थात् नेपाल से आंध्रप्रदेश तक फैला है।

अवस्थाएँ –

1967 में नक्सलवाद का उदय हुआ वंचितों के शोषण की रक्षा करने के लिये लेकिन 1970 में ही बांग्लादेश संकट के कारण आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिये सशस्त्र विद्रोह द्वारा इस आन्दोलन को कुचला गया। 1982 के दशक में इस आन्दोलन का पुनरुत्थान का दौर था और 1990 तक आते-आते यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये बड़ी चुनौति बन गया। 2004 तक का काल उतार-चढ़ाव का काल रहा जो 2012 में चरमोत्कर्ष में बदल गया। 2012 के बाद सरकार द्वारा अपनाई गई 'जीरो टोलरेंस' की नीति के फलस्वरूप आन्दोलन पतन की ओर अग्रसर हो रहा है।

प्रभाव –

नक्सलवादियों का नारा 'सशक्त कृषि का रास्ता ही हमारा रास्ता है' जनआधार का केंद्र बना। फलस्वरूप सर्वप्रथम केरल में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई जन आन्दोलन के फलस्वरूप जमींदारों से जमीन छीनकर वंचितों में वितरित की यह एक

वैचारिक संघर्ष है जिसमें उग्रवाद, आतंकवाद एवं अलगाववाद तीनों का मिश्रण है जो कि वर्ग संघर्ष की विचारधारा का समर्थन करते हुये सर्वहारा का बुर्जुआ के खिलाफ विद्रोह है जिसे वामपंथी उग्रवाद का नाम दिया गया। यह सत्ता एवं व्यवस्था को खुली चुनौति प्रस्तुत करता है तथा साथ ही समानता, न्याय तथा संसाधनों के समान वितरण की पैरवी करता है। नक्सलवाद की उर्वर जमीन अनतर्राज्यीय सीमा, दुर्गम जंगल, पहाड़, आदिवासी क्षेत्र आदि है।

नक्सवादी आन्दोलन के सकारात्मक प्रभाव भी प्रतीत हुये हैं जिसमें विचारधारा की समझ, भूमिहीरनों व वंचितों तथा सर्वहारा के अधिकार, स्वतंत्रता समानता न्याय की स्थापना, समाजवादी सरकार की स्थापना, समाज में समतामूलक व्यवहार, भूमि सुधार, सामन्तवादी सोच में कमी, प्रशासनिक अत्याचार में कमी वंचितों का सशक्तिकरण, आदिवासियों का संगठन, राजनीतिक जवाबदेयता, प्रशासनिक सफलता प्राप्त हुये हैं।

नक्सलवादी आन्दोलन के नकारात्मक प्रभाव अधिक प्रतीत हुये हैं वंचितों के संरक्षक के तौर पर शुरू हुआ यह आन्दोलन संहारक के रूप में स्थापित हो चुका है जो कि स्वार्थी लड़ाई को महत्व देता है जो सरकार के विरुद्ध है। नक्सलवादियों द्वारा बाल नक्सल को बढ़ावा दिया जाता है जिससे अशिक्षा में वृद्धि होती है। नक्सलवादियों द्वारा रक्षा प्राचीर के रूप में महिला व बच्चों को लाया जाता है जिससे उनके जान का भय रहता है। जन अदालत में दी जाने वाली यातनायें अमानवीय व हिंसक होती हैं। नक्सलियों में सत्ता व संसाधन का लालच बढ़ने लगा है जिससे जनसमर्थन कम होने लगा है। सरकार द्वारा चलाये गये सत्वा जुड़ुम आन्दोलन में आदिवासियों ने ही नक्सलवादियों के खिलाफ बढ़क उठाई व उनका दमन किया।

नक्सली क्षेत्र में हमेशा जानमाल का संकट रहता है। नक्सलियों द्वारा सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का भय सदैव बना रहता है। नक्सलियों द्वारा संविधान व संवैधानिक सरकार को चुनौति दी जाती रहती है प्रशासनिक शून्यता, चुनाव सम्पन्न व शांतिपूर्ण करवाने की चुनौति, जनजाति क्षेत्रों में विकास के लिए संसाधनों के दोहन की उनकी स्वीकृति के अनुसार करने की चुनौति रहती है।

नक्सलवाद आज भी जिंदा है क्योंकि यह हमारे समाज के ऐसे खास क्षेत्रों की जरूरतों को पूरी करता है जिन्हें पूरा करने में दूसरा कोई भी दल सक्षम नहीं है। ये क्षेत्र हैं— दलितों और आदिवासियों के तथा ऐसे ही कुछ दूसरे गरीब तबकों के। नक्सलवादियों के इन वर्गों की खासकर स्त्रियों की राज्य तथा स्थानीय प्रभावशाली वर्गों की हिंसा और उनके शोषण में हिफाजत की है। नक्सलवादियों ने इन शोषितों को संगठित किया है । उन्होंने मजदूरी करने वाले दलित, आदिवासी स्त्री, पुरुषों की यूनियन बनाई और संघर्ष करके उनकी आर्थिक हालत को सुधारा जैसे भूमिहीनों की जमीन दिलाना भूमि सुधार किया, खदान मजदूरों की मजदूरी बढ़वाई।

सरकार के प्रयास –

नरम तत्व के बुद्धिजीवियों द्वारा नक्सलवाद के मुद्दे की सामाजिक और विकास संबंधी नीतियों का प्रश्न मानकर निपटाने की बात करते हैं । इन नरम तत्वों में सामाजिक कल्याण विभाग, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास और वन विभाग शामिल हैं। स्वैच्छिक संगठनों का भी उदय हुआ है जो सरकार को गरीबों के हित में नीतियां और कानून बनाने तथा कार्यक्रम लेने का सुझाव देते हैं। ये स्वैच्छिक संगठन नक्सलवाद को सामाजिक समस्या के रूप में बताते हैं।

गरम तत्वों द्वारा कड़े रूखों का समर्थन किया जाता है। इसमें वैधानिक, सुरक्षात्मक, राजनीतिक, प्रशासनिक, प्रयास किये जा रहे हैं । वैधानिक प्रयासों में अनुसूची 5, 6 के तहत जनजाती एवं

अनुसूचित क्षेत्रों के लिये किये गये विशेष प्रावधान, स्वतंत्रता, समानता न्याय की स्थापना, मूल अधिकारों में वंचितों के अधिकार आदि संवैधानिक प्रयास किये गये हैं। कानूनी प्रयासों में आफस्था, निवारक निरोध कानून यथा टाडा, पोटा, रासुका के माध्यम से नक्सलवाद को कम करने के प्रयास किये गये हैं।

प्रशासनिक प्रयासों के अन्तर्गत नक्सलियों से बातचीत, समझौता, सीजफायर, आत्मसमर्पण (आवास, आजीवन रोजगार सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन) चुनाव (पंचायती राज में नक्सलियों को चुनाव में खड़ा है सत्ता का हस्तान्तरण करना) ई-गर्वनेस की स्थापना (पारदर्शिता व जवाबदेयता में वृद्धि), सरकारी कार्यालयों की नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में स्थापना जिससे जनता का भरोसा जीता जा सके। 2016 में मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी की भी मोदी जी द्वारा नक्सलवाद के खिलाफ कार्यवाही कहा गया।

विकासात्मक प्रयासों के अन्तर्गत 30 नक्सल अतिप्रभावी जिलों में आधारभूत संरचना निर्माण के लिये विशेष राशि स्वीकृत की गई। सरकारी योजना 'न्यू इण्डिया' के अन्तर्गत पिछड़े जिलों को विकसित किया जायेगा। पंचायती राज द्वारा स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित करना। रोशनी योजना के तहत कौशल विकास पर बल देना, रोटी, कपडा, मकान के साथ सड़क, बिजली उपलब्धता पर बल दिया जाये। मोबाइल सेवा को सुदृढ बनाना जिससे समायोजन एवं पहुंच सुनिश्चित हो सके।

सुरक्षात्मक प्रयासों के अन्तर्गत सरकार द्वारा कठोर नियमों को अपनाया जाता है। जिसमें बोली नहीं गोली, स्पेशल बटालियन यथा कोबरा, विशेष दल, महिलाओं की बटालियन, सुरक्षा एजेन्सी की सतर्कता, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन ग्रीन हंट प्रमुख हैं। इनमें सेनाओं को नये एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हथियार दिये जाते हैं। नक्सली क्षेत्र में आपदा प्रबंधन का कार्य भी किया जाता है जिससे उनके संसाधन संरक्षित रहे। सरकार द्वारा रणनीतिक प्रयासों के अन्तर्गत काउन्टर प्रोयोगेण्डा (विकास कार्य, स्कूल, बिजली), लोकल गुप्तचर एवं तीव्र विकास को महत्व दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र सेनाओं की तैनाती पर विशेष बल दिया जाता है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ समझौता कर इसरो के साथ भौगोलिक संवेदी प्रणाली तैयार की है। सेना द्वारा विशेष अभियान घेरो, रोको और हथियार न छोडे तो मारो चलाया गया है।

सरकार द्वारा 8 सूत्री कार्यक्रम स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटिजी, ट्रेनिंग सर्विलांस, बिजली टॉवर की उपलब्धता, मुख्य धारा में शामिल करना, स्कूल तक पहुंच एवं वैक्सीन उपलब्ध करवाकर विश्वास प्राप्त किया जा सकता है।

नक्सलियों के प्रति आमजन का स्नेह तोड़ना भी आवश्यक है। संविधान की 5वीं अनुसूची के नियमों को सख्ती से लागू किया जाये जिससे आदिवासी अपने क्षेत्र का अपने हिसाब से नेतृत्व कर सकें। सी.आर.पी.एफ. के लिये हेलीकोप्टर आवंटित किये जाये जिससे वे गतिविधियों पर नजर रख सकें सर्विलांस ड्रोन के साथ-साथ हमलावर ड्रोन भी सेना को उपलब्ध करवाये जाये। बख्तरबंद गाडी, पर्याप्त संख्या में सैनिक, थर्मल इमेजिंग कैमरा, जासूसी उपकरण सेटलाइट निगरानी आदि के माध्यम से इसे नियंत्रित एवं समाप्त किया जा सकता है। यह एक कम्प्यूनिष्ट की विचारधारा है जो वर्तमान में 30 जिलों में माओवादी का राज है जहां उनका अपना कर, भारत सरकार का संविधान नहीं, उनकी सेना, उनका संविधान चलता है।

सुझाव –

संविधान संशोधन कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत ले लिया जाना चाहिये जिससे उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उच्च श्रेणी की आधारभूत संरचनात्मक सुविधायें तैयार की जाये। भूमि सुधार

नक्सलवाद का प्रमुख कारण है इसलिये फारेस्ट एक्ट लागू किया जाना चाहिये। प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय आदिवासियों को समान अधिकार दिये जाये तथा इन अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाये। मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जाये तथा सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाये। सामाजिक व्यवस्था में सामन्तवादी मानसिकता व आर्थिक साधनों पर वर्ग विशेष का आधिपत्य समाप्त किया जाये। जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की सहमति से सेज व पावर प्लांट लगाए व सड़कों का विकास किया जाये तथा उन्हें जिला के ही से जोड़ा जाये। नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में लागू की जाने वाली विकास योजनाओं में नक्सलवादियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

वर्तमान स्थिति –

अपने हक की लड़ाई के लिये शुरू हुआ यह संगठन आज अपने राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ सिद्धि के लिये कार्यरत है। वर्तमान समय में नक्सलवादियों के पास लगभग वह सभी आधुनिक तकनीकी उपलब्ध है जो सीमापार आतंकवादियों और नेपाल के माओवादियों के साथ है।

भारत के कई हिस्सों में नक्सलवादी आन्दोलन आज भी कारगर है क्योंकि समाज में कुछ ऐसे तीखे अंतर विरोध मौजूद है जिन्हें सुलझाने के गंभीर प्रयास नहीं किये जा रहे। दलित आदिवासियों और दूसरे गरीब तबकों के अंदर भारतीय संविधान ने अपनी प्रगति की जो आशाएं जगाई थी उन्हें आज तक किसी भी शासन ने पूरा नहीं किया। सिर्फ जन संघर्षों के जरिए ही इन अंतरविरोधों को हल किया जा सकता है। इन आशाओं को पूरा किया जा सकता है।

एक ऐसी समन्वित नीति अपनायी जाये जिससे नक्सली लोगों को समाज की मुख्य धारा में समाहित किया जा सके क्योंकि टुकड़ों में किया जाने वाला कोई भी प्रयास सीति को दुरुहता ही प्रदान करेगा। कोई स्थायी समाधान नहीं दे पायेगा। इससे यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि नक्सलवाद एक भयंकर राष्ट्रीय सुरक्षा व विकास के समक्ष चुनौति के रूप में सभी के सामने है। इसके फैलाव को रोकने के लिये सरकार ने उचित तैयारी भी की है लेकिन जरूरत है इनको प्रभावी ढंग से लागू करने की तभी नक्सलवाद समाप्त किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. डॉ० जयवीर सिंह : नक्सलवाद का भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव, 2015 पृ.सं. 118-126
2. वीर भारत तलवार : नक्सलबाडी के दोरे में , 2007 पृ.सं. 641
3. B.K. Menon: who are the naxals? A threat to Indian democracy, 2011 पृ.सं. 2014
4. डॉ० लक्ष्मी शंकर यादव : नक्सलवाद का बढ़ता खतरा, 2010 पृ.सं.65
5. डॉ० लक्ष्मी शंकर यादव : नक्सलवाद का बढ़ता खतरा, 2010 पृ.सं.65
6. सिविल सर्विसेज टाईम्स, 2009 पृ.सं. 6-7
7. ए.एस. नारंग : भारतीय शासन व राजनीति पृ.सं. 265
8. पदमसिंह गजराज चेतना गजराज, भारतीय राजनीति राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे और चुनौतियां, 2014 पृ.सं. 209-2016
9. A. Alowageer, sumant swain, manish patel : Naxal Movement an Idcological conflict पृ.सं. 230
10. विवेक एस. राज : नक्सलवाद लालगढ के आइने में : सिविल सर्विसेज टाईम्स 2009 पृ.सं. 6